

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 85/2024

(अपील संख्या – 1592/2020)

डॉ. लक्ष्मी अग्रवाल

—प्रार्थी—अपीलार्थी

## बनाम

- श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
- श्री इकबाल खान, उप शासन सचिव (गुप-1), चिकित्सा शिक्षा, जयपुर (राज.)।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2024

आदेश की दिनांक : 24.10.2024

## उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक

अप्रार्थी—प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

- प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1592/2020 में दिनांक 12.07.2023 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 12.07.2023 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर पैथोलॉजी के पद पर चयन आरपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाकर किया गया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल का भी चयन अपीलार्थी के साथ ही हुआ है। आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट सूची दिनांक 14.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित किया गया है और डॉ. निधी अग्रवाल का नाम क्रम संख्या 18 पर अंकित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेरिट क्रमांक में अपीलार्थी डॉ. निधी अग्रवाल से वरिष्ठ है। आरपीएससी, अजमेर द्वारा सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर के पद का परिणाम एक साथ जारी किया गया है, जिसमें मेरिट क्रमांक भी अंकित किया गया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा औपचारिकताओं (पुलिस वेरिफिकेशन आदि जैसे) में देरी होने के कारण अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के बाद नियुक्ति दिए जाने से उसके मेरिट क्रमांक में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता और न ही अपीलार्थी की मेरिट क्रमांक को उक्त आधार पर बदला जा सकता है। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक डॉ. निधी

अग्रवाल को सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित करने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार कार्मिकों की विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या 21 पर एवं निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल को क्रम संख्या 22 पर नामांकित किया गया है। परंतु आदेश दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों डॉ. निधी अग्रवाल एवं अन्य को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अपीलार्थी को लगभग 8 दिवस विलम्ब से नियुक्ति होने के कारण उसे उक्त पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की पूर्व आचरण रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 06.04.2017 को नियुक्ति देने से उसका परिवीक्षा काल दिनांक 06.04.2018 को पूर्ण होता है और दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अपीलार्थी का परिवीक्षा काल पूर्ण न होने के कारण अपात्र माना जाए। हमारे विनम्र मत में आरपीएससी द्वारा निर्धारित मेरिट क्रमांक के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। यदि विभाग किसी कार्मिक को पूर्व आचरण रिपोर्ट के आधार मात्र के कारण विलम्ब से नियुक्ति प्रदान करता है तो उसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलम्ब से नियुक्ति दी जाने के कारण उसे उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.05.2017 को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की वरिष्ठतानुसार सहायक आचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2018-19 के विरुद्ध पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे और जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ नियमानुसार दिया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।”

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2023 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थी विभाग जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2023 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
3. अप्रार्थी-प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अवमानना कारित नहीं की गयी है। माननीय अधिकरण के आदेशों की

पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी-अपीलार्थी की अवमानना याचिका को निरस्त फरमावे।

4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व अप्रार्थी-प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तथ्यों की पुनरावृत्ति की।
5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2023 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर पैथोलॉजी के पद पर चयन आरपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाकर किया गया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल का भी चयन अपीलार्थी के साथ ही हुआ है। आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट सूची दिनांक 14.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित किया गया है और डॉ. निधी अग्रवाल का नाम क्रम संख्या 18 पर अंकित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेरिट क्रमांक में अपीलार्थी डॉ. निधी अग्रवाल से वरिष्ठ है। आरपीएससी, अजमेर द्वारा सीनियर डिमोन्स्ट्रेटर के पद का परिणाम एक साथ जारी किया गया है, जिसमें मेरिट क्रमांक भी अंकित किया गया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा औपचारिकताओं (पुलिस वेरिफिकेशन आदि जैसे) में देरी होने के कारण अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के बाद नियुक्ति दिए जाने से उसके मेरिट क्रमांक में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता और न ही अपीलार्थी की मेरिट क्रमांक को उक्त आधार पर बदला जा सकता है। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक डॉ. निधी अग्रवाल को सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित करने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार कार्मिकों की विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या 21 पर एवं निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल को क्रम संख्या 22 पर नामांकित किया गया है। परंतु आदेश दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों डॉ. निधी अग्रवाल एवं अन्य को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अपीलार्थी को लगभग 8 दिवस विलम्ब से नियुक्ति होने के कारण उसे उक्त पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की पूर्व आचरण रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 06.04.2017 को नियुक्ति देने से उसका परिवीक्षा काल दिनांक 06.04.2018 को पूर्ण होता है और दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अपीलार्थी का परिवीक्षा काल पूर्ण न होने के कारण अपात्र माना जाए। हमारे विनम्र मत में आरपीएससी द्वारा निर्धारित मेरिट क्रमांक के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। यदि विभाग किसी कार्मिक को पूर्व आचरण रिपोर्ट के आधार मात्र के कारण विलम्ब से नियुक्ति प्रदान करता है तो उसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलम्ब से नियुक्ति दी जाने के कारण उसे उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.05.2017 को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की वरिष्ठतानुसार सहायक आचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2018-19 के विरुद्ध पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे और

*जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ नियमानुसार दिया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।"*

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

*"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

*"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

*"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might*

*arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 12.07.2023 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)